WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

NOVEMBER 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

May millions of lamps illuminate your life with joy, prosperity, health and wealth forever

Wishing you and your family a very Happy Diwali

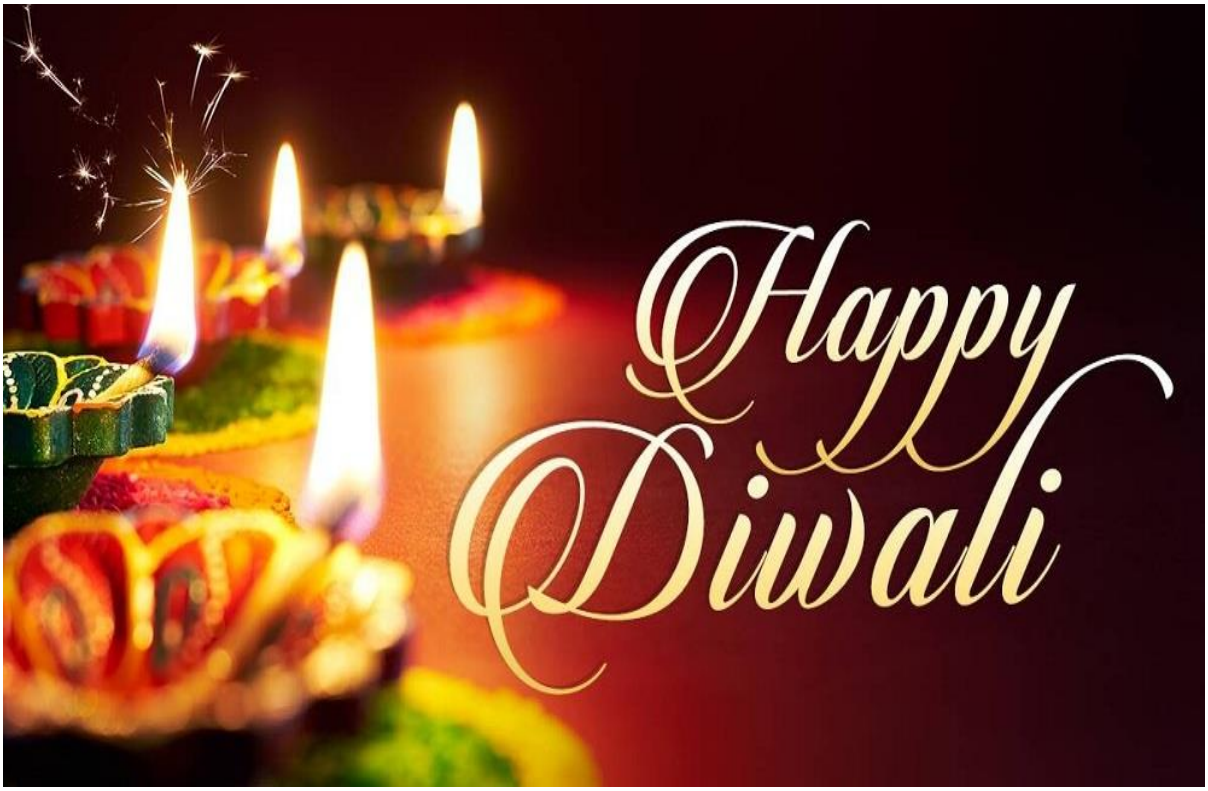

Happy Diwali……

From

Western UP Chamber of Commerce & Industry
Bombay Bazar, Meerut Cantt

INDEX

- आयकर नोटिस की उलझन फ़ोन पर ही सुलझा सकेंगे
- पीएफ से निकासी दावा बार- बार रद्द नहीं होगा
- उद्योग लगाने के लिए नामी कंपनियों को गांव में मिलेगी रियायती जमींन
- डाक से ई- कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन
- मुकदमों की ई- फाइलिंग योजना अग्रिम आदेश तक स्थगित
- बिजली सुधार को पश्चिमांचल में छह से बढ़कर हुए 11 जोन
- माल ढुलाई का अंतरराष्ट्रीय हब बनेगा मेरठ
- एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औधोगिक गलियारों का रास्ता साफ़
- विदेशी निवेश नीति मंजू फार्च्यून- 500 कंपनियों को यूपी में लाने पर फोकस
- **Indian Ports must address infrastructural and operational challenges: Droupadi Murmu**
- **BriskPe Introduces Cross- Border Payments Solution for MSME Exporters**
- **Alert customers in case of change in credit reports: RBI**
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

आयकर नोटिस की उलझन फ़ोन पर ही सुलझा सकेंगे

आयकर विभाग ने कर मांग नोटिस समेत अन्य मामलों में लोगों को जानकारी देने और उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है। इसके जरिए वह खुद आयकरदाताओं को फ़ोन कर जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। अभी कुछ शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। कामयाबी मिलने पर इस योजना को देशव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि कॉल करने के पहले करदाता को इसके बारे में ई- मेल किया जाता है, जिसमे कॉल आने के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उनके खिलाफ टैक्स के बारे में उन्हें सूचित किया जाता है और पूरी प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया जाता है। करदाता अगर चाहता है तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है।

इन शहरों में चल रहे कॉल सेंटर

इसका पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक, गोवा, दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ है। कॉल सेंटर के जरिए पिछले साल 1.4 लाख मामलों का समाधान किया।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

अब तक रिफंड नहीं आया तो यह काम करें

नितिन गुप्ता ने बताया है कि जिन कुछ करदाताओं को आयकर रिफंड में मुश्किल आ रही होगी , उन्हें अपने बैंक की जानकारियां आयकर विभाग के पास सही -सही अपडेट कराने की जरूरत है। उनके मुताबिक ऐसे करीब 35 लाख मामले हैं , जिनमें बैंक की पुष्टि नहीं हो पा रही है। विभाग की तरफ से इन करदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कहीं खाता नंबर गलत है तो कहीं आईएफएससी कोड गलत पाया जा रहा है। साथ ही कई बैंकों के मर्जर के बाद लोगों ने अपनी नई जानकारियां दर्ज नहीं की है। ऐसा करने की वजह से लोगों को रिफंड मिलने में मुश्किल हो रही है।

ईपीएफओ अफसरों को तय समय पर पैसा जारी करने के निर्देश

पीएफ से निकासी दावा बार- बार रद्द नहीं होगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते से धन निकासी की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब क्षेत्रीय कार्यालय धन निकासी के दावों को एक से अधिक बार खारिज नहीं कर पाएंगे। साथ ही दावों को निर्धारित समय में निपटाना होगा। इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

स्पष्ट कारण बताना होगा: इस संबंध में ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संगठन ने संज्ञान लिया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने का कहा है कि निकासी दावे पर जल्द से जल्द काम किया जाए। एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज न किया जाए। प्रत्येक दावे को पहली बार में ही पूरी तरह से जांचा जाए। यदि उसे खारिज किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण सदस्य को बताया जाए। ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सदस्य हैं।

कब कर सकते हैं निकासी

पीएफ खाते में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है या लगातार दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है

तब पूरा पैसा निकाला जा सकता है। वहीं, आपात चिकित्सा, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी आंशिक निकासी की अनुमति होती है।

जिम्मेदारी तय की

ईपीएफओ ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्रीय या अतिरिक्त पीएफ आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में दावों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार होंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने अस्वीकृति दावों की एक रिपोर्ट समीक्षा के लिए भेजें।

यह होती हैं शर्तें

- कम से कम सात वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।
- निकासी की राशि ब्याज सहित कुल अंशदान से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं चाहिए।
- विवाह और शिक्षा के लिए तीन से अधिक निकासी नहीं की होनी चाहिए।

एक सप्ताह में आता है पैसा

धन निकासी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। निकासी दावे को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी जरूरी होती है। प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होती है और एक हफ्ते में पैसा खाते में आ जाता है।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

उद्योग लगाने के लिए नामी कंपनियों को गांव में मिलेगी रियायती जमींन

जमींन आवंटन व्यवस्था में बदलाव की योजना, कैबिनेट की अनुमति का इंतजार

देश-दुनिया की चुनिंदा नामी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अर्जन मूल्य (जमीन को प्राप्त करने में हुआ मालूमी खर्च) पर ग्राम समाज की भूमि देने की तैयारी है। शासन के औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए 'फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति-2023' तैयार कर ली है। ऐसी कंपनियों को कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कार्यवाही शुरू हो गई है।

प्रस्ताव के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली परियोजनाओं व फॉर्चून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 की सूची में शामिल कंपनियों द्वारा 200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट के लिए विशेष रियायत पर भूमि दी जाएगी। पात्र परियोजनाओं को औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वर्तमान आवंटन दरों में रियायत देते हुए भूमि देने की व्यवस्था की जा रही है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

नई व्यवस्था के पक्ष में दलील

यूपी ने 2022-23 में उद्योग बैंक फंड्स को आकर्षित करने में पहला स्थान बनाया है। 2013-14 में यूपी का यह अंश 1.13% था, जो 16.2% हो गया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में करीब 35 लाख करोड़ निवेश के एमओयू हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में यूपी 5वें से दूसरे स्थान पर आ गया है। पांच वर्ष में 3.14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लेकिन, एफडीआई को आकर्षित करने में प्रदेश 11वें स्थान पर है। प्रदेश में मात्र 14 कंपनियां स्थापित हैं जो फॉर्च्यून-500 की सूची में शामिल हैं। तमिलनाडु में ऐसी कंपनियों की संख्या 75 है। इसका अर्थ है कि प्रदेश ने निवेशकों को तो आकर्षित किया है लेकिन बड़े उद्योगों की स्थापना में पीछे है। प्रदेश में उद्योगों के लिए भूमि की वर्तमान दरें अधिक हैं। ऐसे में एफडीआई तथा फॉर्च्यून ग्लोबल व इंडिया-500 कंपनियों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना पहली आवश्यकता है।

भूमि आवंटन मूल्य पर सब्सिडी

प्राधिकरणों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही ग्राम समाज की भूमि के क्षेत्रफल की 50% भूमि इस नीति के तहत पात्र परियोजनाओं को प्राधिकरण के अर्जन मूल्य पर आवंटित की जा सकेगी।

- अन्य प्रकरणों में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूमि आवंटन मूल्य पर सब्सिडी दी जाएगी।
- पश्चिमांचल व मध्यांचल में सब्सिडी की दर 75% तथा बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 80% होगी। बाद में यह सब्सिडी सरकार द्वारा प्राधिकरणों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यह लाभ भी होंगे

- पात्र परियोजनाओं को पूंजी निवेश पर (भूमि की लागत को छोड़कर) 100 करोड़ की वार्षिक सीमा के अंतर्गत सात समान वार्षिक किस्तों में पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। गौतबुद्धनगर व गाजियाबाद में पूंजी निवेश का 25%, इन दो जिलों को छोड़कर

पश्चिमांचल व मध्यांचल में पूंजी निवेश का 30% तथा बुंदेलखंड व पूर्वांचल में पूंजी निवेश का 35% पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

- 100% की दर से एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। यह भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा के बराबर होगी।
- स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट मिलेगी।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5 वर्षों के लिए 100% छूट होगी।
- कंपनी में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5000 रुपये की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार प्रतिपूर्ति देगी।
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट व कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 2.5 करोड़ तक तथा श्रमिकों के आवास/डॉरमेट्री के लिए 10 करोड़ तक मदद दी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय व घरेलू कार्यस्थलों से यूपी में अपनी इकाइयों के संयंत्र लाने पर मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के आयात पर दो करोड़ रुपये परिवहन खर्च दिया जाएगा।

डाक से ई- कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन

देश के विभिन्न शहरों में डाक निर्यात केंद्र खुलने से अब छोटे निर्यातकों को निर्यात करने में काफी आसानी हो रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह है कि छोटे निर्यातकों को विदेश में माल भेजने के लिए अब कस्टम क्लीयरेंस के लिए कस्टम विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। डाक निर्यात केंद्र में ऑनलाइन ही उन्हें कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिल जा रही है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक देश भर में 700 डाक निर्यात केंद्र खोले जा चुके हैं। डाक विभाग ने इस साल के अंत तक 1000 डाक निर्यात केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। डाक विभाग के मुताबिक, खिलौना, स्पोर्ट्स गुड्स, चाय, कॉफी जैसे सामान का डाक निर्यात केंद्र से काफी अधिक निर्यात शुरू हो गया है।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार ने सोमवार को विश्व डाक दिवस के अवसर पर बताया ई-निर्यातकों को पार्सल बुक करने के लिए भी डाक घर आने की जरूरत नहीं है। वे अपने कार्यालय या यूनिट से ही पार्सल बुकिंग कर सकते हैं और डाक विभाग उनके पार्सल को कलेक्ट

कर लेगा। उन्होंने बताया कि ई-निर्यात के जरिए अधिकतम 35 किलोग्राम का सामान भेजा जा सकता है। माल भेजने के लिए अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग शुल्क हैं। ई-निर्यात वाले सामान के ट्रैकिंग के लिए 40 देशों के साथ समझौता किया गया है। कुमार ने बताया कि घरेलू स्तर के कारोबारी भी डाक विभाग की मदद से ई-कामर्स से जुड़ा कारोबार कर सकते हैं। डाक विभाग की बुक नाऊ पे लैटर स्कीम के जरिए कोई भी कारोबारी डाक विभाग के साथ समझौता कर देश भर में कहीं भी अपने सामान को भेज सकता है।

महिला सम्मान बचत स्कीम में 18 लाख से अधिक खाते

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाई गई महिला सम्मान बचत योजना के तहत देश भर में अब तक 18,08710 खाते खोले जा चुके हैं जिसमें 11,546 करोड़ रुपए जमा है। इस साल बजट में महिला सम्मान बचत स्कीम लाने की घोषणा की गई थी।

- छोटे निर्यातकों को क्लीयरेंस के लिए नहीं जाना पड़ता कस्टम विभाग
- डाक निर्यात केंद्र में ऑनलाइन ही मिल जाती है कस्टम क्लीयरेंस

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

मुकदमों की ई- फाइलिंग योजना अग्रिम आदेश तक स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों में हाईकोर्ट व खंडपीठ लखनऊ में दाखिल होने वाले मुकदमों की ई-फाइलिंग योजना पर अग्रिम आदेश तक रोक लग दी है। हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से सभी जिला जजों को इस आशय का ई- मेल भेजा गया है।

हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी पत्र में वादकारियों की सुविधा के लिए प्रदेश की सभी जिला अदालतों में ई- सेवा केंद्रों से ई- फाइलिंग की शुरुआत करने की घोषणा की थी।

ई- फाइलिंग से यह पड़ता प्रभाव

1. हाईकोर्ट में मुकदम दाखिल करने के लिए फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर पर फोटो खिंचाने की अनिवार्यता खत्म हो जाती।
2. अधिवक्ताओं को जारी सीओपी नंबर और एडवोकेट रोल की उपयोगिता खत्म हो जाती।
3. जिला अदालतों के वकील और वादकारी किसी भी जिले से ऑनलाइन मुकदमे दाखिल कर बहस भी कर सकते थे।

बिजली सुधार को पश्चिमांचल में छह से बढ़कर हुए 11 जोन

बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नए सिरे से कवायद की जा रही है। सूबे के विभिन्न डिस्कॉम में पहले 25 जोन थे , अब इनका पुनर्गठन करते हुए 40 कर दिया गया है। पश्चिमांचल के छह जोन से बढ़ाकर 11 जोन कर दिए गए हैं। बिजली सुधार के साथ निगरानी बढ़ाने के लिए नए जोन बनाए गए हैं। बुलंदशहर और नोएडा जोन में कोई फेरबदल नहीं किया गया , लेकिन मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में एक-एक के स्थान पर दो -दो जोन और गाजियाबाद में एक जोन के स्थान पर तीन जोन बना दिए गए हैं।

पीवीवीएनएल अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से निर्णय लेकर बड़े शहर वाले जिलों में महानगर और बाकी नगरीय-ग्रामीण क्षेत्र के अलग जोन बनाए गए हैं। पश्चिमांचल में सर्वाधिक बदलाव गाजियाबाद में हुआ है।

नए जोन में नए पदों का सृजन नहीं होगा: पावर कारपोरेशन अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमांचल में बड़े जोन का विभाजन कर छोटे जोन बनाए गए हैं, इसके के लिए अफसरों, कर्मचारियों के पदों का नया सृजन नहीं होगा। पश्चिमांचल में तैनात अफसरों , कर्मचारियों को नए जोन में जिम्मेदारी देकर कार्य कराया जाएगा।

नए जोन पर एक नजर

मेरठ:

1. विद्युत नगरीय वितरण मंडल मेरठ
2. विद्युत वितरण मंडल प्रथम एवं द्वितीय मेरठ, विद्युत वितरण मंडल बागपत

मुरादाबाद:

1. विद्युत नगरीय वितरण मंडल मुरादाबाद
2. विद्युत वितरण मंडल मुरादाबाद एवं विद्युत वितरण मंडल अमरोहा

सहारनपुर:

1. विद्युत नगरीय वितरण मंडल सहारनपुर एवं विद्युत वितरण मंडल प्रथम एवं द्वितीय सहारनपुर
2. विद्युत नगरीय वितरण मंडल मुजफ्फरनगर, विद्युत वितरण मंडल प्रथम एवं द्वितीय मुजफ्फरनगर, विद्युत वितरण मंडल शामली

गाजियाबाद:

1. गाजियाबाद पहले एक जोन था, जिसे अब तीन जोन में बांट दिया

- प्रदेश के चारों डिस्कॉम में पहले 25 जोन थे , अब नए जोन बनाने के साथ इनकी संख्या 40 हो गई। केस्को में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

माल ढुलाई का अंतरराष्ट्रीय हब बनेगा मेरठ

खेल शहर के रूप में विख्यात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल मेरठ माल ढुलाई का अंतरराष्ट्रीय हब बनेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (आर्थिक गलियारा) पर मोहिउद्दीनपुर के नजदीक मेहरौली गांव में अंतरराष्ट्रीय माल परिवहन हब आकार लेने जा रहा है। अलग- अलग योजनाओं के तहत यह बड़ा केंद्र हो जाएगा।

ईस्टर्न फ्रेट कारिडोर मेरठ से होकर गुजर रहा है। खुर्जा- सहारनपुर वाले हिस्से पर गांव मेहरौली के पास न्यू परतापुर नाम से पासिंग स्टेशन बनाया गया है, जिसमें माल ढुलाई की सुविधा नहीं है। इसी को कुछ सालों में बदलकर डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। यह स्टेशन सामान्य लोडिंग- अनलोडिंग स्टेशन से अलग होगा यानी यहां से आसपास के क्षेत्र का माल चढ़ाया उतारा जाएगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

यह फ्रेट कारिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों व औधोगिक शहरों से जुड़ा है। वहीं, मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के तैयार किए जा रहे सिटी लॉजिस्टिक पार्क बनेगा।

मोहिउद्दीनपुर- मेहरौली से दिल्ली- बागपत रोड को जोड़ेगी नई सड़क:

प्रस्तावित कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क को देखते एक नई सड़क का प्रविधान किया गया है। दिल्ली रोड से बागपत रोड को जोड़ा जाएगा। मोहिउद्दीनपु, मेहरौली समेत कई गावों से होते हुए हाईवे की तरह चौड़ी सड़क बनेगी। मेरठ महायोजना- 2031 में इसका चिन्हाकन किया गया है। इससे दिल्ली रोड व बागपत रोड के माल वाहन देहरादून बाईपास के बजाय इस रोड का उपयोग करेंगे।

कार्गो टर्मिनल और लाजिस्टिक पार्क में यह सुविधा

- ट्रैन और ट्रक से माल पहुंचने की सुविधा होगी।
- वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज रहेंगे।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्माण होगा इसलिए निजी क्षेत्र का ट्रांसपोर्ट क्षेत्र रहेगा।
- विभिन्न देशों व देश के विभिन्न हिस्सों में माल पहुंचने के लिए बुकिंग सुविधा।

जमींन व प्रस्ताव की स्थिति

दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद करनी पड़ेगी। दोनों प्रस्तावों को मेरठ महायोजना- 2031 में शामिल करते हुए भू- उपयोग निर्धारित कर दिया गया है। इससे संबंधित चिन्हित जमींन इसी कार्य के लिए बेचीं जा सकेगी। लाजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव मेडा की ओर से जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। वहीं फ्रेट कॉरिडोर का कार्गो टर्मिनल देश के 100 कार्गो टर्मिनल में शामिल हो चुका है, जिसके लिए जल्द प्रक्रिया शुरू होगी।

इस तरह से मल्टीमॉडल हब बनेगा भूड़बराल- मेहरौली क्षेत्र

- मल्टी माडल यानी विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं को आपस में जोड़ना।
- दिल्ली रोड स्थित मोहिउद्दीनपुर के पास गांव है मेहरौली, जिसमें कार्गो टर्मिनल व लॉजिस्टिक पार्क बनेगा।
- मोहिउद्दीनपुर के पास ही मेरठ विकास प्राधिकरण इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप विकसित करने जा रहा है।
- मोहिउद्दीनपुर से भूड़बराल के बीच की दूरी है 3.50 किमी। भूड़बराल में रैपिड रेल कारिडोर का प्रमुख स्टेशन मेरठ साउथ तैयार हो रहा है। चूंकि रेपिड रेल कारिडोर पर रात में पार्सल ढोने के लिए मालगाड़ी चलेगी, जिसका प्रमुख बुकिंग सेंटर यह स्टेशन होगा।
- भूड़बराल के आसपास ही आइएसबीटी का प्रस्ताव है।
- भूड़बराल के पास ही दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली- देहरादून बाईपास शुरू होता है।
- मोहिउद्दीनपुर के पास ही मोदीनगर क्षेत्र में कंटेनर डिपो है, जहां से मेरठ व गाज़ियाबाद के निर्यातक अपने उत्पाद विभिन्न देशों के लिए बंदरगाहों तक भेजते है।

सिटी लाजिस्टिक प्लान के शार्ट टर्म लक्ष्य में है शामिल

सिटी लाजिस्टिक प्लान को 2024 का लक्ष्य रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यों को शार्ट टर्म, मिड टर्म व लांग टर्म में बांटा गया है। मंडलायुक्त के निर्देश पर शार्ट टर्म प्लान में मेहरौली के लाजिस्टिक पार्क को भी रखा गया है।

हरिद्वार- फरीदाबाद तक का आएगा माल

दौराला और खरखौदा के पास हापुड़ रोड पर भी ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने का लक्ष्य सिटी लाजिस्टिक प्लान में रखा गया है। इन सभी का लक्ष्य हरिद्वार- फरीदाबाद तक का माल यहां से बुक कराने की सुविधा देने का है।

- लाजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के न्यू परतापुर स्टेशन पर माल ढुलाई की सुविधा के लिए भी जल्द विस्तार होगा। ऐसे में दोनों सुविधाएं एक - दूसरे से जुड़ जाएंगी। इससे मेरठ एक बड़ा केंद्र हो जाएगा।

कैबिनेट के फैसले

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औधोगिक गलियारों का रास्ता साफ़

प्रदेश में निर्मित व निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के दोनों तरफ चिह्नित स्थानों पर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के दोनों तरफ चिह्नित स्थानों पर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का निर्णय किया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहीत करने की जिम्मेदारी यूपीडा को सौंपी गई है, लेकिन उसके पास इसके लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव है। इस समस्या से निपटने के लिए यूपीडा को 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का कैबिनेट ने निर्णय किया है।

पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे 18 और बस अड्डे: प्रदेश में परिवहन निगम के 18 और बस अड्डों को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने के लिए पुनः

निविदा आमंत्रित करने तथा इसके लिए टेंडर की शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन 18 बस अड्डों की तरह विकसित किया जाएगा। इनमें मेरठ बस अड्डा शामिल हैं।

ईट व मिट्टी के बर्तन से जुड़े पट्टाधारकों को मशीन से खोदाई की मिली अनुमति:

प्रदेश में ईट व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले पट्टाधारकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार व हरियाणा की तर्ज पर अब दो मीटर तक की मिट्टी की खोदाई मशीन से की जा सकेगी और यह खनन संहिता के दायरे में नहीं आएगी। अब तक की व्यवस्था के तहत पट्टाधारक को सिर्फ हस्तचालन प्रक्रिया के माध्यम से ही खोदाई की अनुमति थी।

'वंदन' से होगा सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों का विकास लखनऊ: नगरीय क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास 'वंदन' योजना के तहत करवाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश भी तय करने की मंजूरी दे दी गई है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

सहकारी मिलों की सीसी लिमिट के लिए बैंक गारंटी को मंजूरी: सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2023- 24 के लिए उप्र सहकारी बैंक लिमिटेड व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट (सीसी) को शासकीय गारंटी प्रदान करने से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जीएसटी का अतिरिक्त खर्च यूपीडा वहन करेगा

कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया है कि केंद्र सरकार की ओर से निर्माण कार्यों पर जीएसटी की दर बढ़ाए जाने के कारण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं पर परियोजना की 30 वर्ष की कन्सेशन अवधि के दौरान पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार को यूपीडा वहन करेगा। इसके लिए यूपीडा को बजट के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2022 को निर्माण कार्यों पर जीएसटी की दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया था।

विदेशी निवेश नीति मंजू फार्च्यून- 500 कंपनियों को यूपी में लाने पर फोकस

यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित के लिए कैबिनेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। इसके तहत और फार्च्यून-500 कंपनियों को जमीन खरीदने, स्टांप ड्यूटी और पूंजीगत निवेश में छूट मिलेगी। स्टेट जीएसटी में सौ फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एफडीआई के माध्यम से प्रदेश में निवेश बहुत कम है। अन्य राज्यों की तुलना में यह केवल 9435 करोड़ रुपए था, इसलिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर

प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 के तहत स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मे पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट में छूट

यदि निवेश करने वाली कंपनी को कैपिटल गुड्स के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलता है तो यूपी जीएसटी अधिनियम-2017 के अंतर्गत आईटीसी की स्वीकार्य सीमा तक निवेश अवधि के अंदर एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा। कंपनी को रिफंड की तय सीमा तक एसजीएसटी के बकाये लेजर में से आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ये रिफंड उत्पादन की तारीख से पांच साल तक सालाना किस्त के रूप में दिया जाएगा।

बड़ा रोजगार, ढेरों रियायतें

- जमीन की लागत छोड़कर पूंजी निवेश पर 100 करोड़ सालाना सब्सिडी 7 साल तक।
- परियोजनओं को 100% एसजीएसटी सब्सिडी।
- इकाई द्वारा एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट या कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की लागत का 50 फीसदी या 2.5 करोड़ की सब्सिडी।
- परियोजना के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास की लागत का 10 करोड़ रुपये तक 7 सालाना किस्तों में दिया जाएगा।
- संयंत्रों को यूपी में लाने पर 2 करोड़ रुपये परिवहन लागत या आयात शुल्क में छूट।

युवाओं का होगा कौशल विकास

प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने के एवज में योगी सरकार पांच वर्ष तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि कंपनियों को देगी। इस योजना के तहत अधिकतम 500 लोगों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस पर सरकार 15 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मौजूदा इकाइयों को उप्र लाने में सब्सिडी

अपनी मौजूदा इकाइयों को विदेश या देश के अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने वाली फर्मों को मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के आयात पर अधिकतम दो करोड़ रुपये प्रति इकाई तक की परिवहन लागत की आधी रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के बाद एकमुश्त दी जाएगी। पेटेंट पंजीकरण के लिए भी निवेशकों को शुल्क व्यय की 75 प्रतिशत राशि एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी। घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 20 लाख रुपये होगी।

मेरठ समेत छह शहरों में नई आवासीय योजना

प्रदेश सरकार ने अयोध्या समेत कुल छह बड़े शहरों में नई आवासीय योजना शुरू करने का फैसला किया है। ये योजनाएं अयोध्या के अलावा वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा और मुरादाबाद में जल्द शुरू की जाएंगी । इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवास विकास परिषद और संबंधित शहरों के विकास प्राधिकरणों द्वारा लाई जाएंगी । योजनाओं के जमीन की खरीदने के लिए सरकार दोनों संस्थाओं के 1580 करोड़ रुपये देगी।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

बता दें कि शहरों में बढ़ती आबादी के चलते बढ़ रही आवासीय समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 100 शहरों में नई टाउनशिप योजना शुरू करने का फैसला किया है। नई टाउनशिप बसाने और उसे विकसित करने के लिए भूमि अर्जन की लागत का 50 प्रतिशत शासन अधिकतम 20 साल के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आवास विभाग दो किस्तों में पैसा देता है। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इसे 12.5 एकड़ कर सकती है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- 1580 करोड़ रूपये दिए जाएंगे परिषद और प्राधिकरणों को

Indian Ports must address infrastructural and operational challenges: Droupadi Murmu

The operational efficiency and turnaround time of Indian ports need to match the globel average benchmark to exploit the full potential of the maritime sector, said President of India Droupadi Murmu .

Speaking at the eight convocation of the Indian Maritime University (IMU) in Chennai. Murmu said, “India does not figure in the top 20 nations when it comes to the annual port calls. On the list of 50 best container ports worldwide, we only have two. The Indian ports must address infrastructural and operational challenges befor they graduate to the next level. The majority of our fishing fleet is yet to be mechanised.”

Detailing the need to overcome several challenges faced by the sector, she quoted as example the fact that “a lot of container ship cargo is diverted to nearby foreign ports due to depth restrictions. In the merchant and civilian shipbuilding industry, we need to aim for the highest standards of efficiency, efficacy and competitiveness.”

Citing the sagarmala programme. Murmu said it was a significant move away from port development to port- led development. “The five pillars of “port-led development” envisaged by sagarmala are port modernisation, port connectivity, port-led industrialisation, coastal community development and coastal shipping or inland water transportation.

Tamil Nadu Governor R N Ravi said India had grown from tenth to third economy in the world and “we will be a developed country by 2047. Maritime and industry and maritime economy will play a role in this journey.”

Union minister of Ports, shipping and waterways sarbananda sonowal said coastal cargo grew 102% and ports are experiencing double digit growth. He also said that ‘Amrit Kaal Vision 2047’ would help the country to become a global maritime hub.

BriskPe Introduces Cross- Border Payments Solution for MSME Exporters

Mumbai, Oct 31 BriskPe has launched cross-border payments solution, particularly for Micro, Small and Medium-sized enterprise (MSME) exporters.
The Mumbai-based cross-border payments platform is poised to transform the landscape where the hurdles of high transaction costs, exchange rate fluctuations, and payment delays have long thwarted businesses' international aspirations.
BriskPe aims to eliminate the burden of excessive transaction fees and the unpredictability of exchange rates.
"Our mission is clear to revolutionise cross-border payments and bring the world closer for Indian businesses. With the launch of BriskPe, we're empowering entrepreneurs, MSMEs, and the entire business landscape to flourish on the global stage like never before," said Sanjay Tripathy, Co-Founder & CEO of BriskPe.
BriskPe's approach offers exporters an opportunity to thrive in the global market. By removing the financial and administrative complexities associated with cross-border transactions, BriskPe is transforming the way businesses approach international trade, making it more accessible and lucrative for all.
"At BriskPe, our vision is to simplify international trade to the level of local commerce. We believe that every local business in India has the potential to flourish on the global stage. With our innovative solutions, we're leveling the playing field and empowering local businesses to compete globally without the traditional barriers and complexities," Tripathy said.

India-Bangladesh Gives 12-hour Window Time For Border Trade

India and Bangladesh customs officials have extended time for border trade via Changrabandha in Cooch Behar district by two hours in the morning. From now, exporters and importers of both countries get a 12-hour window from 6am to 6pm.

The decision was made at a high-level meeting held in Changrabandha on Monday between senior Customs officials of India and Bangladesh, and senior officials of the Border Security Force and the Border Guard Bangladesh.

A number of officials from Bangladesh including Abdul Alim, a deputy commissioner of Bangladesh Customs, Abdul Latif, the superintendent of Customs posted in Burumari as well as the officials of the BSF and the BGB were present at the meeting.

The transit route, through which goods from India and Bhutan are sent to Bangladesh by road and vice-versa, connects Burimari on the other side of the border in Bangladesh.

"So far, the movement of trucks through the border was allowed from 8am to 6pm. In today's (Monday's) meeting, it has been decided that trucks can cross the border on both sides from 6am to 6pm. The decision, we feel, will boost bilateral trade among the countries through this border," said Nima Lhamu Sherpa, the assistant commissioner of Customs posted in Changrabandha.

Every day, around 300 trucks from India carry various goods to Bangladesh using this route. Also, another 100 trucks from Bangladesh use the same route to bring goods to India.

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103

Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035

Fax: 0121-2441009

Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

Alert customers in case of change in credit reports: RBI

NEW DELHI: The Reserve Bank of India (RBI) has instructed banks and financial institutions to inform customers whenever they submit information to credit bureaus about default or delays in payment of loans. The banking regulator has also asked the credit bureaus to alert the customers when their credit reports are accessed by a third party.

In a new set of instructions on Thursday, the RBI has asked credit bureaus to provide easy access to full credit report including credit score to individuals whose credit history is available once every year free of cost. The report should be available with the credit bureau by displaying the link prominently on the home page of their website so that individuals are able to access their credit report conveniently.

In case a customer requests for data correction in his/her credit report, and the same has been rejected by the bank, then the bank must inform the customers the reasons for the rejection to enable the customer to better understand the issues in the report. Banks have been asked to have a dedicated nodal point or official of contact for credit bureaus for redressal of customer grievances.

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXX